भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

12.03.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2140 का उत्तर

कारगिल के लिए बेहतर संपर्क

2140. श्री मोहम्मद हनीफ़ा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के कारगिल जिले को रक्षा की दृष्टि से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित होने और इसे देश के बाकी भागों से जोड़े जाने की तत्काल आवश्यकता के दृष्टिगत कश्मीर के गांदरबल को कारगिल से जोड़ने के लिए शीघ्र ही सर्वेक्षण कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार/केंद्र शासित प्रदेश-वार/ जिला-वार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/जिले की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाएं लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम स्थान तक पहुंच संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों एवं वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के विस्तार, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफॉरवर्ड तथा धन की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

sk

2016-17 में श्रीनगर-कारगिल-लेह (480 कि.मी.) नई रेल लाइन का सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की अनुमानित लागत 55,896 करोड़ रूपए थी। बहरहाल, कम यातायात अनुमानों के कारण परियोजना का कार्य आगे नहीं किया जा सका।

रक्षा मंत्रालय द्वारा बिलासपुर-मनाली-लेह नई लाइन, जो आंशिक रूप से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ती है, को सामरिक लाइन के रूप में चिह्नित किया गया है। बिलासपुर-मनाली-लेह नई लाइन परियोजना (489 कि.मी.) का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत ₹1,31,000 करोड़ रूपए है।

****

sk